

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,

प्रमुख सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,

उधमसिंहनगर।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 25 अगस्त, 2008

विषय:-मै0 अमान आईस फैक्ट्री के नाम से उद्योग लगाने हेतु ग्राम रहमापुर तहसील जसपुर (जनपद उधमसिंहनगर) की खतौनी संख्या 55 के खसरा नम्बर 171 मि0 की क्षेत्रफल 0.129 हेक्टेयर भूमि कय की अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1071/सात-स0भू0अ0/2008 दिनांक 07 अप्रैल, 2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री शशिविन्द कुमार सैनी पुत्र श्री तोताराम सैनी निवासी आजादनगर गली नं0-1 रेलवे हरथला कालोनी मुरादाबाद एवं मौ0 फेजान कुरैशी पुत्र हाजी इरफान कुरैशी निवासी भूडा चौराहा असालतपुरा मुरादाबाद उ0प्र0 को जिलाधिकारी के उपरोक्त पत्र के द्वारा संस्तुत ग्राम रहमापुर तहसील जसपुर (जनपद उधमसिंहनगर) की खतौनी संख्या 55 के खसरा नम्बर 171 मि0 की क्षेत्रफल 0.129 हेक्टेयर भूमि मै0 अमान आईस फैक्ट्री के नाम से कय की अनुमति उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(V) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

1- केंता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।

2- केंता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा, तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3- केंता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (आईस फैक्ट्री की स्थापना) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ कय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

- 4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।
- 5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।
- 6- शासन द्वारा दी गई भूमि कय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी। प्रश्नगत उद्योग की स्थापना के सम्बन्ध में स्पॉट जोनिंग क्षेत्र के लिये निश्चित सिद्धान्त/नीतियों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।
- 7- कय की जाने वाली भूमि का भू-उपयोग नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर निर्धारित नीति /मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए औद्योगिक प्रयोजन हेतु फैंक्ट्री भवन निर्माण का प्लान सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात ही प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- 8- प्रस्तावित उद्योग का निर्माण कार्य राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) 2005 में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप किया जायेगा।
- 9- प्रस्तावित औद्योगिक इकाई में प्रदेश के स्थायी निवासियों को नियमित रूप से 70 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।
- 10- इकाई में पूंजी निवेश/निर्माण से पूर्व पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड तथा अग्निशमन विभाग आदि से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
- 11- प्रस्तावित स्थल पर अवस्थापना विकास से सम्बन्धित कार्यों का दायित्व सम्बन्धित इकाई को होगा। यह अनापत्ति/ सहमति पैकेज के अन्तर्गत देय सुविधाओं के लिये आधार के रूप में उद्भूत नहीं की जा सकेगी।
- 12- कय की जाने वाली भूमि का उपयोग मात्र आईस फैंक्ट्री उद्योग की स्थापना के लिए किया जायेगा।
- 13- प्रस्तावित परियोजना के लिये कय की जाने वाली भूमि भारत सरकार से अधिसूचित नहीं है तथा इकाई द्वारा विनिर्मित किये जाने वाला उत्पाद भी थ्रस्ट उद्योग में सम्मिलित नहीं है। अतः प्रस्तावित उत्पाद के विनिर्माण पर भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज के अन्तर्गत प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहन सुविधाओं का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
- 14- किसी दशा में प्रस्तावित कंटाओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि कय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

15- भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

16- इकाई की स्थापना के पूर्व उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य वांछित विधिक एवं अन्य अनापत्तियां/अनुज्ञायें/प्रमाण पत्र आदि नियमानुसार प्राप्त कर लिये जायेंगे।

17- उक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या: भू0कय/18(1)/2008-1(61)/2008 एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून

2- आयुक्त, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।

3- सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

4- सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

5- सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

6- निदेशक, उद्योग, इन्ड्रिस्ट्रियल इस्टेट, पटेलनगर, देहरादून।

7- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीडा, 2-न्यूकैन्ट रोड, सिडकुल, देहरादून।

8- श्री शशिचन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री तोताराम सैनी निवासी आजादनगर गली नं0-1 रेलवे हरथला कालोनी मुरादाबाद एवं मौ0 फेजान कुरैशी पुत्र हाजी इरफान कुरैशी निवासी भूडा चौराहा असातपुरा मुरादाबाद उ0प्र0।

9- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय।

10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।